भारत सरकार
शक्षा मंत्रालय
उच्चतर शक्षा वभाग

लोक सभा
अतारां कत प्रश्न संख्या-1257
उत्तर देने की तारीख-**08/12/**2025

एनआईआरएफ इं डया रैं कंग 2025

†1257. श्री खलीलुर रहमान:

क्या शक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे क:

(क) नेशनल इन्स्टीट्यूशन रैं कंग फ्रेमवर्क (एनआईआरएफ) इं डया रैं कंग 2025 के अनुसार देशभर के इंजीनियरिंग संस्थानों की राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार सूची का ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या सरकार ने अनुसंधान कार्यक्रमों के कार्यान्वयन और पर्याप्त बुनियादी ढाँचा सु वधाओं का आकलन कया है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) संस्थान शक्षण, अ धगम और संसाधन, अनुसंधान और व्यावसायिक कार्य के साथ-साथ स्नातक परिणाम के एनआईआरएफ मापदंडों को पूरा करना सुनिश्चित करने के लए सरकार द्वारा क्या पहल की गई है; और
(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

शक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री
(डॉ. सुकान्त मजूमदार)

(क) से (घ): उच्चतर शक्षा संस्थानों (एचईआई) के बीच सकारात्मक प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने के लए, भारत सरकार ने वर्ष **2015** में इन एचईआई की वा षक रैं कंग (जिसे इं डया रैं कंग कहा जाता है) हेतु राष्ट्रीय संस्थागत रैं कंग फ्रेमवर्क (एनआईआरएफ) शुरू कया था। भारत रैं कंग की कार्यप्रणाली पाँच व्यापक मापदंडों अर्थात शक्षण, अ धगम और संसाधन," "अनुसंधान और व्यावसायिक कार्य," "स्नातक परिणाम," "प्रसार और समावे शता," और सहकर्मी धारणा पर आधारित है।

इंजीनियरिंग श्रेणी में स्थान प्राप्त संस्थानों की सूची एनआईआरएफ वेबसाइट https://www.nirfindia.org/Rankings/2025/EngineeringRanking.html पर उपलब्ध है।

भारत सरकार देश भर में शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए संस्थागत विकास, क्षमता वृद्धि, अनुसंधान हेतु संसाधनों की सर्वसुलभता और नवाचार संवर्धन को बढ़ावा देने के लिए ठोस प्रयास कर रही है। कुछ पहलें निम्नलिखित हैं:

केंद्रीय वित्तपोषित उच्चतर शिक्षा संस्थानों को बजटीय सहायता के अतिरिक्त, भारत सरकार उच्चतर शिक्षा अभियान (रूसा)/प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान (पीएम-उषा) योजना के अंतर्गत तीन घटकों नामतः चुनिंदा राज्य विश्वविद्यालयों में गुणवत्ता और उत्कृष्टता को बढ़ाना, "विश्वविद्यालयों को बुनियादी ढांचा अनुदान और उच्चतर शिक्षा में सुधार के लिए बहु-विषयक शिक्षा और अनुसंधान विश्वविद्यालय (मेरु) के अंतर्गत राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता भी प्रदान करती है।

इसके अतिरिक्त, अनुसंधान और विकास से एकीकृत शैक्षणिक, औद्योगिक और उद्यम सृजन के उद्देश्य से, इन संस्थानों के आस-पास अनुसंधान परिस्थितिकी बनाने के लिए प्रमुख एचईआई में अनुसंधान पार्क बनाए गए हैं। ये अनुसंधान पार्क औद्योगिक इकाइयों से वित्तपोषित अनुसंधान को आसान बनाते हैं, जिससे औद्योगिक-शैक्षणिक सहयोग को बढ़ावा मिलता है। वर्ष **2014** से, सरकार ने **6** नए अनुसंधान पार्क बनाए हैं, जिनमें से एक आईआईटी दिल्ली, आईआईटी कानपुर, आईआईटी गुवाहाटी, आईआईटी हैदराबाद और आईआईएससी बैंगलोर तथा आईआईटी गांधीनगर में है।

भारत के बड़े अकादमिक संस्थानों में उच्च गुणवत्तापूर्ण अनुसंधान को जारी रखने के लिए सर्वोत्तम प्रतिभाओं को आकृष्ट करने के उद्देश्य से, सरकार ने वर्ष **2018-19** में प्रधान मंत्री अनुसंधान फेलो (पीएमआरएफ) योजना शुरू की, जिसका कुल वित्तीय परिव्यय रुपये **1650** करोड़ था।

साथ ही, एचईआई में अनुसंधान गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए, **6000** से अधिक एचईआई ने अनुसंधान और विकास प्रकोष्ठ स्थापित किए हैं।

एनईपी **2020** के सिद्धांतों के अनुरूप, गणितीय विज्ञान, इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण और पृथ्वी विज्ञान, स्वास्थ्य एवं कृषि समेत प्राकृतिक विज्ञान के क्षेत्र में अनुसंधान, नवाचार और उद्यमशीलता के लिए उच्च स्तरीय कार्यनीतिक निदेश प्रदान करने हेतु अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन (एएनआरएफ) को एक शीर्ष निकाय के रूप में स्थापित किया गया है।

केंद्रीय एजेंसी के समन्वय द्वारा राष्ट्रीय अंशदान के माध्यम से केंद्रीय या राज्य सरकार के प्रबंधन वाले सभी उच्चतर शिक्षा संस्थानों और केंद्रीय सरकार के अनुसंधान विकास संस्थानों के सभी विषयों के विद्यार्थियों, संकाय सदस्यों, अनुसंधान कर्ताओं और वैज्ञानिकों के बड़े समूह तक विद्वानों की शोध पत्रिकाओं तक पहुँच बनाने के लिए सरकार ने ओएनओएस योजना अनुमोदित की है। इस योजना के तहत **6300** से ज़्यादा ऐसे संस्थान कवर किए गए हैं। इस योजना के लिए **3** कैलेंडर वर्ष, **2025, 2026** और **2027** के लिए कुल लगभग **6,000** करोड़ रुपये आबंटित किए गए हैं।

शिक्षा मंत्रालय ने सार्वजनिक और निजी श्रेणी के **10** उच्चतर शिक्षा संस्थानों को उत्कृष्ट संस्थान (आईओई) का दर्जा देने और उन्हें विश्व स्तरीय शिक्षण और अनुसंधान संस्थान के रूप में उभरने में सहायता प्रदान करने के लिए विश्व स्तरीय संस्थान योजना की है। अब तक बारह संस्थानों को आईओई के रूप में अधिसूचित किया गया है। इनमें **08** सार्वजनिक श्रेणी के संस्थान और **04** निजी श्रेणी के संस्थान शामिल हैं। इस योजना के तहत केवल सार्वजनिक संस्थानों को ही निधि प्रदान की जाती है। योजना शुरू होने के बाद से **08** लोक संस्थानों के लिए लगभग **6198.99** करोड़ रुपये की राशि संस्वीकृत की गई है।

इसके अतिरिक्त, स्वास्थ्य, दीर्घकालिक शहरों और कृषि के तीन क्षेत्रों में अंतर विषयक अनुसंधान करने, अत्याधुनिक एप्लिकेशन तैयार करने और व्यापक समाधान करने के लिए, सरकार ने वित्तीय वर्ष **2023-24** से वित्तीय वर्ष **2027-28** के समय में रुपये **990.00** करोड़ के कुल वित्तीय परिव्यय के साथ आर्टिफिशयल इंटेलिजेंस (एआई) में तीन उत्कृष्टता केंद्र (सीओई) स्वास्थ्य, दीर्घकालिक शहरों और कृषि के क्षेत्र में एक-एक स्थापित करने का अनुमोदन कर दिया है। आईआईटी मद्रास में **500** करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ शिक्षा के क्षेत्र में एक एआई सीओई को संस्वीकृत प्रदान की गई है।

'तकनीकी शिक्षा में बहुविषयक शिक्षा और अनुसंधान सुधार' योजना को **275** तकनीकी संस्थानों में कार्यान्वित करने का अनुमोदन प्रदान किया गया है, जिसमें **175** इंजीनियरिंग संस्थान हैं और **100** पॉलिटेक्निक संस्थान शामिल हैं। इस योजना का उद्देश्य राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 (एनईपी-2020) के अनुरूप पहलों को कार्यान्वित करके सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में तकनीकी शिक्षा की गुणवत्ता, समानता और शासन को बेहतर बनाना है।

यह एक 'केन्द्रीय क्षेत्र योजना' है जिसका वर्ष **2025-26** से वर्ष **2029-30** की अवधि के लिए कुल वित्तीय प्रभाव **4200** करोड़ रुपये है।

विभिन्न योजनाओं के मूल्यांकन के एक भाग के रूप में आउटपुट-आउटकम निगरानी फ्रेमवर्क (ओओएमएफ) के तहत विभिन्न योजनाओं की परिणाम-आधारित निगरानी की जाती है।

*****